

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून दिनांक 25 नवम्बर, 2010

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में पैक्स मिनी बैंकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1253/XIV-1/2010-5(44)/2010 दिनांक 19 अगस्त, 2010 के क्रम में आपके पत्र संख्या:-3710/नियो0/कारपस फण्ड/2010-11 दिनांक 25 सितम्बर, 2010 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-187/XXVII (1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में पैक्स मिनी बैंकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत अवशेष ₹ 9,89,000/- (रूपये नौ लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) उक्त योजना का शासनादेश संख्या:- 6938-43/व0ग्रा0वि0/सह0/2003-04 दिनांक 17 मार्च 2004 के निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली 2004 के शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त योजना का 31 मार्च को जमा निक्षेप का वार्षिक अंशदान 0.30 प्रतिशत के अनुसार (वर्ष दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर) अनुमन्य होगा।

(3) प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक एवं शीर्ष बैंक के अंशदान जो कि क्रमशः 0.15, 0.10 एवं 0.05 (वर्ष के दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर) है, जमा किया जाय। उक्त योजना का अनुश्रवण दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जाय तथा उसकी प्रगति से शासन को भी अवगत करायें।

(4) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह के अन्त में या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से

(2)

अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या -18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय-10-पैक्स मिनी बैंको में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या- 295(P)/XXVII -4/2010 दिनांक 04 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या:-1639(1)/XIV-1/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उपसचिव।